RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 26 जून 2024 वर्ष 06 अंक 69 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनधिकृत पब के खिलाफ बुलडोजर चलाने का दिया आदेश

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

ओबीसी समुदाय के कुछ डॉक्टरों ने आरक्षण कोटा और लाभ छोड़ने की इच्छा जताई

मुंबईः महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा हुआ। इस बीच ओबीसी समुदाय के कुछ डॉक्टरों ने आरक्षण कोटा से मिलने वाले लाभों को छोड़ने की इच्छा जताई है। इन्हीं में से एक है 40 वर्षीय ओबीसी डॉक्टर राहुल घुले। डॉ.राहुल ने आरक्षण को इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है। इस पत्र में डॉक्टर राहुल ने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए आरक्षण कोटा और उससे मिलने वाले लाभों को छोड़ने की इच्छा जताई है। डॉ.राहुल वंजारी समुदाय से आते हैं और ठाणे में 'एक रुपया क्लिनिक' चलाते हैं। उनका मानना है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न लोग आरक्षण छोड़ देते हैं तो यह जरूरतमंद गरीबों को इसका लाभ मिलेगा और सामाजिक तनाव कम होगा।

एक रुपया क्लिनिक चलाते हैं डॉ.राहुल

डॉ.घुले मराठवाड़ा के धाराशिव से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता एक शिक्षक हैं। उन्होंने 2003 में मुंबई के जी एस मेडिकल कॉलेज में ओबीसी-एनटी कोटा के तहत दाखिला लिया था और एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। पिछले 16 साल से वो मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉ.घुले की शादी एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से हुई है। 2017 में ठाणे में 'एक रुपया क्लिनिक' शुरू करने वाले डॉ.घुले अब मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई क्लीनिक चलाते हैं।

डॉ.राहुल ने किया ये दावा

डॉ.राहुल घुले का दावा है कि 2008 में उनके द्वारा स्थापित ओबीसी मेडिकोस एसोसिएशन के कम से कम 15 अन्य डॉक्टर भी अपने जाति प्रमाण पत्र वापस करना चाहते हैं। ये सभी आरक्षण कोटा छोड़ना चाहते हैं। नियमों के अनुसार, अगर किसी ओबीसी परिवार की तीन साल की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह 'क्रीमी लेयर' में आता है। उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन, डॉक्टर घुले और उनके साथी इस कदम को एक सामाजिक संदेश देने के रूप में देखते हैं।

'मराठा-ओबीसी आंदोलन ने समाज में दरार पैदा की'

डॉ. घुले का मानना है कि मराठा-ओबीसी आंदोलन ने समाज में दरार पैदा कर दी है। अगर अमीर लोग अपना आरक्षण छोड़ देते हैं तो आरक्षण गरीबों को मिलेगा और ऐसे विवाद खत्म होंगे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने 'आरक्षण छोड़ो, समाज जोड़ो' अभियान भी शुरू किया है।

इन डॉक्टरों ने भी किया आरक्षण छोड़ने का फैसला

डॉ. घुले के साथ काम करने वाले डॉक्टर वैभव मलवे और अनिल चौधरी ने भी आरक्षण छोड़ने का फैसला किया है। कल्याण में रहने वाले डॉ.मलवे सोनार समुदाय से आते हैं, जबकि धुले के रहने वाले अनिल चौधरी तेली समुदाय से हैं। डॉ. मलवे कहते हैं कि हमारी जाति तो जीवन भर वही रहेगी। लेकिन एक बार आर्थिक रूप से मजबूत हो जाने के बाद हमें

विपक्ष के सांसदों ने हाथ में संविधान थामकर लोकसभा में ली शपथ

नई दिल्ली : अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरूआत हो चुकी है. संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली. इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों ने अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली. कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और सदस्यों को शपथ दिलाई. महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी शरद गुट और उद्धव गुट की शिवसेना के सांसदों ने अलग-अलग भाषा में शपथ ली. किसी ने हिंदी में शपथ ली तो किसी ने मराठी में शपथ ली. वहीं शपथ के दौरान कांग्रेस के नंदुरबार सांसद एडवोकेट गोवाल कागदा पाडवी, कांग्रेस की धुले सांसद बच्छाव शोभा दिनेश, सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे के हाथों में संविधान की कॉपी थी.

इसके अलावा कांग्रेस के अमरावती सांसद बलवंत बसवंत वानखड़े, कांग्रेस रामटेक सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे, भंडारा-गोंदिया सांसद डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले, कांग्रेस के गढ़चिरौली-चिमूर सांसद डॉक्टर किरसान नामदेव, चंद्रपुर की कांग्रेस सांसद धानोरकर प्रतिभा सुरेश उर्फ बालूभाऊ ने भी आज शपथ ली.

अन्य राज्यों के कांग्रेस सांसदों ने भी दिया ये संदेश

विपक्षी सदस्य 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन की बैठक में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे थे. असम के धुबरी से निर्वाचित कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ पढ़ी. बिहार के सासाराम से कांग्रेस के सदस्य मनोज कुमार ने भी अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ग्रहण की. हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया था. उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संविधान बदलना चाहती है.

डेयरी किसानों ने जाम किया हाइवे; दूध के दाम बढ़ाने की कर रहे डिमांड

अहमदनगर : दूध के दामों को लेकर महाराष्ट्र के डेयरी किसानों ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया है. 25 जून को दूध के सही दाम ना मिलने के विरोध में किसानों ने सुबह स्टेट हाइवे जाम कर दिया. हाइवे जाम होते ही श्रीरामपुर, अहमदनगर से संगमनेर को जाने वाले वाहनों की लम्बी-लम्बी लाइन लग गई. सैंकड़ों डेयरी किसान हाथों में तख्ती लेकर सड़क के बीचों-बीच खड़े हो गए. डेयरी कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. कंपनियों पर डेयरी किसानों संग दोहरा बर्ताव करने का आरोप लगाया. वहीं सरकार से दूध के सही दाम दिलाने की मांग करने लगे. काफी देर तक रास्ता रोको अभियान चलता रहा. गौरतलब रहे महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक शेतकरी संघटन ने रास्ता रोको अभियान की शुरूआत की है. संघटन के वाइस प्रेसिडेंट अजित दादा काले का कहना है अभियान महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में 15 जुलाई तक चलेगा. डेयरी किसानों का आरोप है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पड़ोसी राज्यों के मुकाबले डेयरी किसानों को दूध के बहुत कम रेट दिए जा रहे हैं. साथ ही किसानों को कोऑपरेटिप में भी शामिल नहीं किया जा रहा है.

दो घंटे तक रोका श्रीरामपुर हाइवे

वाइस प्रेसिडेंट अजित दादा काले ने किसान तक को बताया कि आज सुबह तय कार्यक्रम के तहत सैंकड़ों डेयरी किसान श्रीरामपुर से संगमनेरी को जाने वाले हाइवे पर पहुंच गए थे. देखते ही देखते हाइवे को जाम कर दिया. नारेबाजी शुरू कर दी. हमारी सरकार से मांग है कि दूध के जो दाम डेयरी किसानों को दूसरे राज्यों में दिए जा रहे हैं वही महाराष्ट्र में भी दिए जाएं. अभी महाराष्ट्र के डेयरी किसानों को गाय के दूध के दाम 26 रुपये लीटर के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र वाली कंपनियां ही गाय का दूध 34 से 37 रुपये लीटर तक खरीद रही हैं.

कांग्रेस एमएलसी चुनाव के लिए दिल्ली में बैठक

मुंबईः महाराष्ट्र विधान परिषद से 27 जुलाई को 11 विधायक रिटायर हो जाएंगे. विधायक महाराष्ट्र विधान सभा सदस्यों के मतदान के माध्यम से परिषद के लिए चुने गए थे. केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन 11 सीटों के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. विधानसभा में संख्या बल के मुताबिक फिलहाल महायुति के 9 और महाविकास अघाड़ी के 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं.

सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कांग्रेस किसे मौका देगी. विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में एक बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि विधान परिषद चुनाव में किसे उम्मीदवारी मिलेगी. कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं.

कांग्रेस किसे देगी मौका ?

वजाहत अतहर मिर्जा और डॉ. प्रज्ञा सातव और दोनों विधायक

रिटायर हो रहे हैं. उम्मीद है कि दोनों को एक और मौका मिलेगा. इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान, मुजफ्फर हुसैन, संध्या सव्वलाखे, भिवंडी कांग्रेस नेता दयानंद चोरगे और सूरज ठाकुर के नाम की चर्चा है. इससे पहले हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी और चंद्रकांत हंडोरे को मौका दिया था. इसलिए देखना होगा कि इस बार कांग्रेस किसे मौका देती है.

विधान परिषद से कौन होगा रिटायर ?

बीजेपी से विजय गिरकर, निलय नाइक, रमेश पाटिल, राम राव पाटिल, महादेव जानकर, शिवसेना से ठाकरे ग्रुप से अनिल परब, शिवसेना से मनीषा कायंदे, कांग्रेस से डॉ. वजाहत मिर्जा, प्रज्ञा सातव, बाबाजानी दुरानी और जयंत पाटिल रिटायर हो रहे हैं. इन 11 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

आर्थिक सक्षमता की तस्वीर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए सप्ताह भर बाद पूरे सात साल हो जाएंगे। एक लंबी कशमकश के बाद ही इस कर व्यवस्था ने आकार लिया था। जीएसटी जैसी व्यवस्था का सुझाव पहली बार वर्ष 2000 में विजय केलकर टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद सामने आया था, लेकिन चूंकि यह एक अत्यंत जटिल मुद्दा था तो इस पर व्यापक सहमति बनाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। इसी कारण जीएसटी को साकार रूप लेने में लगभग सत्रह वर्ष लग गए। अपने पहले कार्यकाल में इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही। इसने कई प्रकार के केंद्रीय एवं राज्यों के करों को एकीकृत करके टैक्स व्यवस्था को सुगम एवं सहज बनाने का काम किया। अभी जीएसटी की 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत दरों की चार श्रेणियां हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं इसके दायरे से मुक्त हैं। इस एकीकृत कर व्यवस्था ने कई पड़ावों पर लगने वाले विभिन्न करों की जगह एकबारगी कर भुगतान को सुनिश्चित किया। इससे समग्र कर बोझ घटने के साथ ही आर्थिक सक्षमता बढ़ी है। इसके माध्यम से कर संग्रह भी निरंतर बढ़ रहा है। इस साल मई में 1.73 लाख करोड़ रुपये जीएसटी के जरिये प्राप्त हुए। यह राशि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रही। चूंकि जीएसटी के मूल स्वरूप में कई प्रविधानों को इसके आरंभ में शामिल नहीं किया गया था तो इस कर व्यवस्था में सुधारों की भी रह-रहकर चर्चा जोर पकड़ती रहती है। इसी सिलसिले में जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर चर्चा की। जिस समय जीएसटी लागू हुआ था तब वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी ऐसे प्रस्ताव की वकालत की थी। अब इस मुद्दे ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। जीएसटी के व्यापक स्वरूप को देखा जाए तो ऐसी कोई भी पहल बहुत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने के मुद्दे पर राज्यों ने आरंभ से ही हिचक दिखाई है। इसकी वजह भी बहुत सीधी है कि उन्हें इन उत्पादों से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। अलग-अलग राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी सहूलियत के हिसाब से वैट लगाया है। वहीं केंद्र सरकार प्रति लीटर के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाती है, जिसकी दरें पूरे देश के लिए एकसमान होती हैं। केंद्र और राज्यों के सम्मिलित करों-ड्यूटी से उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। यदि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आएं तो आवश्यक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के चलते देश भर में एकसमान कीमतें संभव हो सकती हैं। इससे जिन राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम हैं, वहां उनमें बढ़ोतरी की आशंका होगी, जिसके अपने राजनीतिक जोखिम होंगे। साथ ही साथ जिन राज्यों में कीमत अत्यधिक ऊंची है, वहां दाम गिर जाएंगे। यदि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी का हिस्सा बनाया जाए तो इसके कई फायदे देखने को मिलेंगे। इससे जहां आर्थिक सक्षमता बढ़ेगी, वहीं उपभोक्ताओं का भी भला होगा। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर बहुस्तरीय कर व्यवस्था लागू है। इससे कीमतों का एक जटिल एवं मनमाना ढांचा बन गया है। इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में मानक दरें लागू होंगी और कीमतों के स्तर पर विसंगतियां समाप्त होंगी। जीएसटी में आने से करों का स्तर घटने से कीमतें नरम होने की संभावना है। इससे आम लोगों से लेकर व्यापारिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। एकसमान जीएसटी दर से कीमतों के मोर्चे पर पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जब सभी राज्यों में एकसमान कर व्यवस्था लागू होगी तो एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार का विकास होगा, जो कि जीएसटी के मूलभूत उद्देश्यों में से एक रहा है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

नागपुर/ कामठी मंडी में प्याज के अधिकतम दाम 4000 और औसत दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल

नागपुर : महाराष्ट्र में प्याज का दाम लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन एक मंडी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है उसका नाम है कामठी. यह मंडी नागपुर में है और यहां पिछले एक हफ्ते से लगातार 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव बना हुआ है. राज्य की कुछ और मंडियों में भी 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट पहुंचा है लेकिन ऐसा सिर्फ एक-दो दिन के लिए ही हुआ है. जबकि कामठी में यह रेट लगातार कायम है. महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार नागपुर की कामठी मंडी में 24 जून को सिर्फ 15 क्विंटल प्याज की आवक हुई. यहां आवक में भारी कमी की वजह से न्यूनतम दाम भी 3000 रुपये क्विंटल हो गया. अधिकतम दाम 4000 और औसत दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

आवक में कमी की वजह से राज्य की ज्यादातर मंडियों में प्याज का दाम 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल तक बना हुआ है. इससे किसानों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है. किसान आमतौर पर प्याज का 3000 रुपये क्विंटल का दाम मांगते रहे हैं और इस साल उन्हें अधिकांश मंडियों में इतना दाम मिल रहा है. किसानों का कहना है कि उनकी लागत प्रति क्विंटल 2000 रुपये आती है, इसलिए उन्हें कम से कम 3000 रुपये का भाव मिलना चाहिए.

कसि मंडी में कतिना है दाम

खेड़ की मंडी में 25 जून को सर्फि 300 क्विंटल प्याज की आवक हुई. यहां न्यूनतम दाम 300, अधिकतम 3000 और औसत दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

अकोला मंडी में 624 क्विंटल प्याज की आवक हुई. यहां न्यूनतम दाम 1500, अधिकतम 3400 और औसत दाम 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार चंद्रपूर मंडी में 311 क्विंटल प्याज की आवक हुई. यहां न्यूनतम दाम 3000, अधिकतम 3800 और औसत दाम 3500 रुपये प्रति क्विंटल रहा. सतारा मंडी में 276 क्विंटल प्याज की आवक हुई. इसकी वजह से यहां पर न्यूनतम दाम 2000, अधकितम 3000 और औसत दाम 2500 रुपये प्रति क्विंटल रहा.

निर्यात से शर्त हटाए सरकार

महाराष्ट्र के किसान चाहते हैं कि सरकार अब दोबारा प्याज की निर्यातबन्दी न करे. क्योंकि बहुत मुश्किल से सही कीमत मिलनी शुरू हुई है. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि अभी सरकार ने निर्यात पर 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) और उस पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है. इस शर्त को हटाने की जरूरत है, जिससे किसानों को और अच्छा दाम मिल सके.

मनसे करा रही है 288 सीटों का सर्वे
अमित ठाकरे को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी

मुंबईः महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि पार्टी राज्य की सभी 288 सीटों का सर्वे करा रही है। अब तक 88 सीटों पर सर्वे का काम पूरा हो गया है। वहां पर संभावित उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज ठाकरे जुलाई में प्रदेशभर का दौरा करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में मनसे किसके साथ गठबंधन करेगी? इस पर बताया गया कि गठबंधन करना है या फिर अकेले दम पर चुनाव में उतरना है। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार विमर्श करेंगे। आगामी चुनाव प्रचार में में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी।

यूपी-बिहार जैसे हालत

कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज ने कहा कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज हमारी हमारी बैठक महत्वपूर्ण थी। सभी को उनकी जिम्मेदारी से अवगत करा दिया गया है। इस पर आगे भी चर्चा की जाएगी। राज ने कहा कि राज्य में जाति और धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। ऐसा करने वाले को उसका फायदा लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में जाती-पाती में लोगों को बांटा जा रहा है उससे तो महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी होने लगेगी। जाती के नाम पर राज्य में खून खराबा होने लगेगा, जो बहुत ही खतरनाक है।

रसिया और यूक्रेन के प्रचार करने नहीं जाऊंगा

राज से जब पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में किसका प्रचार करेंगे तब राज ने अपने अंदाज में कहा कि रसिया और यूक्रेन के प्रचार करने नहीं जाऊंगा। बाद में राज ठाकरे ने सोशल मीडिया '' पर लिखा कि जो दोस्त एक साथ कूड़ा उठाने का काम करते हैं, एक साथ लंच बॉक्स खाते हैं, वे एक-दूसरे को जातिसूचक नजरों से देखने लगते हैं। स्कूल-कॉलेजों में यही स्थिति है। महाराष्ट्र के हर युवा को शांति से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा खेल कैसे खेला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र कभी स्थिर नहीं होगा।

कंगना रनौत के सीएम सूट पसंद करने पर भड़के संजय राउत

मुंबईः हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर नया विवाद खड़ा गया है। शिवसेना (ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने फिल्म कंगना रनौत पर निशान साधते हुए कहा है कि कंगना को सीएम सूट की क्या जरूरत है? उन्हें राष्ट्रपति भवन में जगह दी जानी चाहिए। राउत का यह बयान उन रिपोर्ट्स पर आया जिनमें यह कहा गया है कि कंगना रनौत दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का दौरा किया, जहाँ उन्हें सीएम का सूट पसंद आया और उन्होंने प्रशासन से अस्थायी रूप से रहने के लिए यह विशेष सूट मांगा। प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम सूट किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र सदन के अधिकारियों ने उन्हें सीएम सूट देने से मना कर दिया गया।

राणे ने राउत पर किया पलटवार

कंगना रनौत के सीएम सूट मांगने को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर राणे ने राउत पर पलटवार किया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि कल कंगना राणावत ने महाराष्ट्र सदन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। इसलिए वह चली गईं, लेकिन मैं संजत राउत को कहना चाहता हूं कि वह एक चुनी हुई सांसद हैं। उनकी तरह से बैकडोर से नहीं पहुंची हैं। राणे ने सवाल दागा कि जब जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब सचिन वाजे वर्षा के बंगले पर कितने समय तक रुके थे? आप वही उत्तर कब देंगे? हमाम में सब नंगे हैं ज्यादा बात मत करो।

नई फिल्म को लेकर हैं सुर्खियों में

मंडी से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी का रोल किया है। रनौत की इमरजेंसी फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दिखेगी। मणिकर्णिका फिल्म बैनर के तले बनी इस फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल हैं। कंगना रनौत मंडी से जीत का सांसद बन चुकी हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा है।

एनसीपी (शरद पवार) ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र; चुनाव चिन्हों को हटाने का किया अनुरोध

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर एनसीपी (एसपी) के चुनाव चिन्ह से मिलते-जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने का अनुरोध किया है। एनसीपी (एसपी) ने आयोग से अनुरोध किया है कि पिछले साल उन्हें जो 'तुतारी' चिन्ह आवंटित किया गया था, वह 'पिपानी/तुरही'से मिलता है। उसे चुनाव चिह्नों से बाहर कर दिया जाए।

एक जैसे चुनाव चिन्हों की वजह से हुआ नुकसान

एनसीपी (एसपी) का दावा है कि यह चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी के चुनाव चिन्हों से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते हैं। शरदचंद्र पवार की पार्टी ने तर्क दिया कि निर्दलीय उम्मीदवारों को ह्तुरहा/तुतारीह्व जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित करने से एनसीपी (एसपी) को काफी नुकसान हुआ है और यह समान अवसर बनाने के सिद्धांत के खिलाफ है।

एनसीपी (एसपी) ने निर्वाचन आयोग से लगाई गुहार

बता दें कि एनसीपी में बंटवारे के बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों से पहले एनसीपी (सपा) को 'तुतारी' प्रतीक दिया था। अपनी याचिका में एनसीपी (एसपी) ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले इन भ्रामक चुनाव चिन्हों को तुरंत वापस ले लें या हटवा दें।

राज्यपाल ने 'गेटवे टू द सी: हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन' नामक पुस्तक का अनावरण किया...

मुंबई: राजभवन मुंबई में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुंबई क्षेत्र की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री रमेश बैस ने क्षेत्र के प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए 'गेटवे टू द सी: हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन' नामक पुस्तक का विमोचन किया।

पुस्तक लॉन्च एवं सम्मान समारोह

पुस्तक लॉन्च कार्यक्रम को कई उल्लेखनीय क्षणों द्वारा चिह्नित किया गया था:

विमोचन: राज्यपाल रमेश बैस ने आधिकारिक तौर पर पुस्तक का अनावरण किया।

सम्मान: राज्यपाल ने मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी (एमएमएमएस), 17 लेखकों और पुस्तक में योगदान देने वाले दो संपादकों को सम्मानित किया।

प्रस्तुति: राजभवन के दरबार हॉल में पुस्तक की विस्तृत प्रस्तुति

दी गई।

सहयोग: यह कार्यक्रम एशियाटिक सोसाइटी के साथ साझेदारी में प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

किताब के बारे में

'गेटवे टू द सी' एक व्यापक कार्य है जो मुंबई क्षेत्र के समुद्री इतिहास की पड़ताल करता है:

प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

संकलक: मारिटाइम मुंबई म्यूजियम सोसायटी

सामग्री: प्रसिद्ध लेखकों के 18 लेख

फोकस: मुंबई क्षेत्र के ऐतिहासिक बंदरगाह और डॉक्स

इस पुस्तक के विमोचन समारोह में कई प्रतिष्ठित मेहमान मौजूद थे, जिनमें कैप्टन के डी बहल (मारिटाइम मुंबई म्यूजियम सोसायटी के अध्यक्ष), वाइस एडमिरल (संघर्षरत सेवा अवर्ती) इंद्रशील राव, डॉ। शेफाली शाह (संपादक), अनीता येवाले (उपाध्यक्ष), संगीता गोडबोले (प्रकाशन विभाग के उप निदेशक), सहयोगी लेखक शामिल थे।

राज्यपाल का अभिभाषण

अपने संबोधन में, राज्यपाल रमेश बैस ने समुद्री इतिहास के महत्व पर जोर दिया:

उन्होंने मुंबई के नागरिकों को अपनी प्राचीन समुद्री विरासत के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल ने ऐतिहासिक ज्ञान के संरक्षण और प्रचार में पुस्तक की भूमिका पर प्रकाश डाला।

प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं

'गेटवे टू द सी' की रिलीज का स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है:

ऐतिहासिक शोध: यह मुंबई के समुद्री अतीत में और अधिक शोध को जन्म दे सकता है।

पर्यटन: पुस्तक मुंबई के आसपास के ऐतिहासिक समुद्री स्थलों में रुचि बढ़ा सकती है।

शैक्षिक मूल्य: स्कूल और विश्वविद्यालय पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं।

सांस्कृतिक गौरव: यह मुंबईवासियों में अपने शहर के समृद्ध इतिहास के बारे में गर्व की भावना पैदा कर सकता है।

मुंबई: नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश; पूरी तरह से विचार करने के बाद कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कोरोना काल के दौरान प्राण वायु प्रोजेक्ट घोटाले में शामिल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मुंबई नगर निगम से मंजूरी मांगी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सोमवार को नगर निगम प्रशासन को आदेश दिया कि वह पूरी तरह से विचार करने के बाद ही यह मंजूरी दे। इसलिए नगर निगम की ओर से कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि पुलिस के अनुरोध का जल्द ही जवाब दिया जाएगा. घोटाले में शामिल होने के आरोपी कर्मचारियों ने म्युनिसिपल इंजीनियर्स एसोसिएशन और म्युनिसिपल मजदूर यूनियन और वकील हर्षवर्द्धन

सूर्यवंशी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। साथ ही मांग की है कि जब तक नगर निगम की ओर से विभागीय जांच नहीं हो जाती, तब तक पुलिस को इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इजाजत न दी जाए.

आरोप है कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न अस्पतालों और कोरोना केंद्रों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए एक निश्चित कंपनी को छूट दी गई थी, जिसे कथित तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा शुरू कर दी गई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में थी, तब इस संबंध में नियमों की अनदेखी के आरोप में नगर निगम के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

याचिका के मुताबिक, कोरोना काल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी मांग थी. हालाँकि, इसकी भारी कमी थी। इसलिए, एलएनजी प्लांट के निर्माण की अनुमति तुरंत दे दी गई।

ठाणे - यात्रियों की जान से खिलवाड़; निजी बस मालिकों का आंदोलन, 100 बसें जमा

ठाणे- खराब कोच बेचने के बाद भी मरम्मत में लापरवाही; बस खरीदारों की बात न सुनने से नाराज मुंबई बस ओनर्स एसोसिएशन और बस मालिक सेवा संघर्ष समिति के सदस्य आक्रामक हो गए। इन बस मालिकों ने सोमवार को मुंबई के नायगांव स्थित कंपनी के सर्विस सेंटर में जाकर अपनी 100 से ज्यादा बसें जमा करा दीं. दिलचस्प बात यह है कि इन बसों को जमा करने के बाद भी अशोक लेलैंड की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वाहन मालिकों ने बारिश में ही धरना प्रदर्शन किया है.

अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा बाजार में लाई गई 13.5 मीटर लंबी बसों को निजी ट्रांसपोर्टरों ने करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर खरीदा है। लेकिन इन बसों के खराब होने से सफर के दौरान हादसों का खतरा बढ़ गया है। इस संबंध में मुंबई बस ओनर्स एसोसिएशन ने 13 जून को ठाणे में अशोक लीलैंड कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। और बसों की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की और रास्ता निकालने का अनुरोध किया। हालाँकि, प्रबंधन ने उनके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया।

100 बसें सर्विस सेंटर पर जमा हो गईं

अशोक लीलैंड की कई बसें टूटे हुए फ्रंट व्हील हब, टूटे व्हील डिस्क, क्लच-प्रेशर प्लेट, रिलीज बियरिंग, क्लच सिलेंडर, टूटे डीजल पाइप, टूटे साइलेंसर पाइप, टूटे हुए सप्लाई पाइप, टूटे हुए गियर बॉक्स - ब्रेक लाइनर से पीड़ित हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये समस्याएं महज कुछ ही महीनों में पैदा हुई हैं। अशोक लीलैंड कंपनी कोई सुविधा या वारंटी प्रदान नहीं करती है। ऐसे में हताश करीब 100 बस मालिकों ने आज अपनी बसें सीधे सर्विस सेंटर पर लौटा दी हैं।

ठाणे: आवारा कुत्ते की संदिग्ध मौत, वागले इस्टेट थाने में मामला दर्ज

ठाणे: वागले एस्टेट के मनोरोग क्षेत्र में एक आवासीय भवन के परिसर में चार से पांच महीने के आवारा कुत्ते का शव संदिग्ध अवस्था में मिला. पशु प्रेमी संगठन का आरोप है कि कुत्ते को जहर देकर या बेरहमी से पीटकर मारा गया है. तदनुसार, वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मनोरोग क्षेत्र में एक आवासीय भवन है। बिल्डिंग परिसर में चार माह का कुत्ता बेहोश मिला। इस घटना की जानकारी पशु प्रेमी संस्था ए लाइफ फॉर एनिमल फाउंडेशन को मिली. संस्था की अध्यक्ष सोनाली वाघमारे ने जब कुत्ते की जांच की तो कुत्ते के मुंह से झाग निकल रहा था. वे तुरंत कुत्ते को मुंबई के एक पशु चिकित्सालय ले गए। डॉक्टरों ने कुत्ते को मृत घोषित कर दिया.

संस्था के सदस्यों ने जब डॉक्टरों से कुत्ते की मौत के बारे में पूछा तो बताया गया कि कुत्ते की मौत जहरीला खाना खाने या फिर ज्यादा पिटाई से हुई होगी. इसके बाद सोनाली ने इस मामले की शिकायत वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. उसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

कल्याण : सेंट थॉमस स्कूल को पेड़ काटने के लिए नोटिस

कल्याण - कल्याण पूर्वी विजयनगर इलाके में सेंट थॉमस स्कूल ने कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के पार्क विभाग से अनुमति लिए बिना स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक पुराने बादाम के पेड़ को काट दिया। नगर पालिका के पार्क विभाग ने स्कूल प्रबंधन को कार्रवाई का नोटिस भेजकर सात दिन के भीतर इस अवैध कार्रवाई का खुलासा करने का आदेश दिया है।

मथाडी, व्यापारी आक्रामक; नवी मुंबई नगर निगम पर धड़क मार्च

नवी मुंबईः नवी मुंबई नगर निगम ने मुंबई कृषि उपज बाजार समिति में खतरनाक इमारतों को ध्वस्त करने के लिए 20 जून से प्याज और आलू बाजार का नल कनेक्शन काट दिया था। लेकिन 20 जून से अब तक बाजार के स्टॉल, व्यापारी और अन्य बाजार तत्व पानी के बिना परेशान थे। इसलिए, मथाडी नेता नरेंद्र पाटिल ने मथाडी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ एक हड़ताल मार्च दिया था और उन्हें पानी की आपूर्ति बहाल करने या सड़कों पर उतरकर विरोध करने की चेतावनी दी थी। इस दौरान नगर आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्याज और आलू बाजार में पानी की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी.

वर्ष 2005 से प्याज आलू मंडी को नवी मुंबई नगर निगम की खतरनाक सूची में शामिल किया गया है। इस बाजार समिति का पुनर्विकास पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है. पिछले साल उम्मीद थी कि प्याज और आलू बाजार का पुनर्विकास तेजी से होगा, लेकिन सवाल अभी भी लंबित है। वहीं दूसरी ओर यहां के व्यापारियों के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण पलायन की समस्या अब भी बनी हुई है. इसलिए, उच्च जोखिम सूची में शामिल होने के बाद भी, वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यापारी झुग्गियों को खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो खतरनाक इमारतों को कैसे गिराया जाए? ऐसा सवाल उठाया गया है. नवी मुंबई नगर निगम हर साल एपीएमसी को खतरनाक इमारतों का नोटिस भेजता है। इस साल भी नवी मुंबई नगर निगम की ओर से यह नोटिस दिया गया है और 30 साल पुरानी इमारतों की संरचना का निरीक्षण करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है. लेकिन दूसरी ओर, नवी मुंबई नगर निगम ने खतरनाक इमारतों को ध्वस्त करने के लिए प्याज आलू बाजार, मैपको बाजार और मसाला बाजार के साथ-साथ प्रशासनिक भवन में पानी की आपूर्ति में कटौती की थी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनधिकृत पब के खिलाफ बुलडोजर चलाने का दिया आदेश

पुणेः पुणे के फर्ग्यूसन रोड पर एक पब में युवाओं के ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई. पुणे पोर्श कार दुर्घटना के बाद, पुणे में बार और पब जनता के गुस्से का विषय थे। इसके बाद उनका ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल होने से पब कल्चर की हर तरफ आलोचना हो रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को फोन किया और उन्हें शहर में अनधिकृत पबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को नशीली दवाओं से संबंधित पबों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने और पुणे को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए नए सिरे से अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, ''पुणे को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए अनधिकृत पबों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को नशीली दवाओं से संबंधित पब पर अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया गया है।''

दो दिन पहले पुणे के फर्ग्यूसन रोड पर लिक्विड, लाइगर, लाउंज (एल3) पब के वॉशरूम में कुछ युवाओं द्वारा ड्रग्स लेने का वीडियो प्रसारित होने के बाद हड़कंप मच गया था। आधी रात के बाद पब खुला होने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. पुलिस ने पब मालिक, ड्राइवर, मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

नीट परीक्षा परिणाम में धांधली

एटीएस ने जिला परिषद स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार और चार अन्य पर केस दर्ज

मुंबईः महाराष्ट्र में भी कथित नीट धांधली का कनेक्शन मिला है और इस मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने एक जिला परिषद स्कूल के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में चार अन्य लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि पैसे देकर नीट परीक्षा पास करने के इच्छुक छात्रों की मदद करने के लिए एक रैकेट चलाया जा रहा था। मामले में एटीएस की तरफ से जिन चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनमें दो शिक्षक लातूर जिले के, एक नांदेड और एक दिल्ली का निवासी है।

पुलिस ने कुल चार लोगों पर दर्ज किया केस

जानकारी के मुताबिक लातूर जिले के दो शिक्षक संजय तुकाराम जाधव और जलील खान उमर खान पठान, नांदेड के इरन्ना मश्नाजी कोंगलवाव और दिल्ली के रहने वाले शख्स गंगाधर पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एक शिक्षक जलील खान उमर खान पठान को रविवार की देर रात गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

गुप्त सूचना पर एटीएस ने की कार्रवाई

एटीएस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग पैसे के बदले में नीट छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए अवैध रैकेट चला रहे हैं। इसके बाद एटीएस ने पूछताछ के लिए शनिवार रात को लातूर से जाधव और पठान को हिरासत में लिया। लातूर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के मोबाइल फोन में नीट 2024 परीक्षा से संबंधित संदिग्ध जानकारी मिली।

तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी

मामले में पुलिस ने कहा, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलील खान उमर खान पठान के रूप में हुई है, जबकि अन्य तीन फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

ठाणे : गड्ढों से परेशानी, बारिश में मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम

ठाणेः ठाणे, घोड़बंदर और खारेगांव इलाकों में जिन राजमार्गों और फ्लाईओवरों की मरम्मत पिछले साल की बारिश के बाद की गई थी, उनमें इस साल पहली बारिश में ही बड़े-बड़े गड्ढे हो गए। इससे राज्य सड़क विकास निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के शासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। इन गड्ढों के कारण दुर्घटना की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है. सरकार के संबंधित विभागों द्वारा ठाणे शहर की उपेक्षा के कारण नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है। हालाँकि, ठाणे महालिका प्रशासन आलोचना का स्वामी बन गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणेकरों की यात्रा को गड्ढों से मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के माध्यम से ठाणे नगर निगम को 605 करोड़ रुपये का फंड दिया है। इसके चलते शहर के अंदरूनी हिस्सों में कई सड़कों का नवीनीकरण किया गया।

इससे तस्वीर से पता चलता है कि इस मानसून के मौसम में शहर के भीतर की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि, हर साल की तरह इस साल भी ठाणे और घोड़बंदर इलाके से गुजरने वाले हाईवे के साथ-साथ फ्लाईओवर पर भी गड्ढे हैं।

पिछले साल बरसात के दौरान इस सड़क पर गड्ढे हो गए थे। गड्ढों वाली यात्रा को लेकर नागरिकों के आक्रोश जताने के बाद यह अनुमान लगाया गया कि सड़क की मरम्मत हो जाने से इस मानसून सीजन में सड़क गड्ढा मुक्त हो जायेगी. नगर निगम क्षेत्र में कोपरी फ्लाईओवर, तिनहाट नाका फ्लाईओवर एमएमआरडीए, नितिन कंपनी फ्लाईओवर एमएसआरडीसी, माजीवाड़ा, कपूरबावड़ी, मानपाड़ा, वाघबील फ्लाईओवर लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में गुटबाजी

मुंबईः लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में सब ठीक लग रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में गुटबाजी उभरकर सामने आने लगी है। मुंबई कांग्रेस के एक खेमे ने वर्षा गायवाड हटाओ मुहिम शुरू कर दी है। मुंबई कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली हाईकमान को पत्र लिखकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड के कामकाज पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत बनाना है और इसके लिए गायकवाड के पास समय नहीं है।

'वर्षा ने 13 महीने तक कुछ नहीं किया'

पार्टी सूत्रों का दावा है कि गायकवाड को मुंबई कांग्रेस का प्रमुख बने हुए करीब 13 महीने हो गए हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी कैडर को प्रेरित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं की है। इससे पहले मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूषण पाटिल ने भी दावा किया है कि आम चुनाव में उन्हें मुंबई कांग्रेस यूनिट से कोई मदद नहीं मिली। 16 जून को लिखे पत्र में कांग्रेस नेतृत्व से विधानसभा चुनाव और मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर शहर में पार्टी को पुनर्जीवित करने पर चर्चा के लिए वक्त मांगा। सूत्रों ने बताया कि इनमें से ज्यादातर नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल तथा राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं।

पत्र पर कांग्रेस किन नेताओं ने किया है हस्ताक्षर

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, 16 जून को लिखे पत्र में एक राज्यसभा सदस्य चंद्रकांत हंडोरे, मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख जनार्दन चंदुरकर और भाई जगताप, महाराष्ट्र कांग्रेस कार्याध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम खान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश शेट्टी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु चव्हाण, मुंबई कार्याध्यक्ष चरणसिंह सप्रा, महाराष्ट्र कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अमरजीत मन्हास, महाराष्ट्र कांग्रेस महासचिव जाकिर अहमद, बीएमसी में पूर्व प्रतिपक्ष नेता रवि राजा, भूषण पाटील, शिवजी सिंह, युसुफ अब्राहिनी, संदेश कोंडविलकर और शशिकांत बनसोडे ने हस्ताक्षर किया।

अवैध संबंध के चलते महिला की हत्या, प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज

वसईः विरार में एक शादीशुदा महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. इस मामले में विरार पुलिस ने आधी रात को महिला के बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. महिला, धनश्री अंबाडस्कर (32), विरार के फूलपाड़ा में साईनाथ अपार्टमेंट में रूपेश अंबाडस्कर (37) और दो युवा बेटियों, नेत्रा और नव्या के साथ रहती थी। सोमवार की सुबह उसका पति रूपेश काम पर गया था और दोनों बेटियां स्कूल गयी थीं. दोपहर में धनश्री की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दोपहर में उसका बॉयफ्रेंड शेखर कदम उससे मिलने घर आया. मृतक धनश्री के पति रूपेश ने आरोप लगाया है कि जब उनके बीच विवाद हुआ तो कदम ने धनश्री की गला दबाकर हत्या कर दी.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com